



## भारत का वमिानन क्षेत्र

### प्रलिमिंस के लयि:

[क्षेत्रीय संपरक योजना-उडान \(UDAN\)](#), [ओपन सकाई समझौता](#), [वसतु एवं सेवा कर \(GST\)](#), [कारबन तटसथता](#), [डजिी यात्रा](#)

### मेन्स के लयि:

भारत के वमिानन क्षेत्र का परविरतन, सरकारी नीतयिँ और हसतक्षेप

[सरोत: इंडयिन एक्सपरेस](#)

## चरचा में क्योँ?

भारतीय वमिानन क्षेत्र में लंबे समय तक अग्रमि भूमिका नभाने वाली कंपनी इंडगिो अब भारतीय हवाई अड्डों से बनिा-रुके, लंबी दूरी और कम लागत वाली उडानों के साथ वशि्वस्रतर पर अपनी पहचान बनाने का प्रयास कर रही है।

- हालाँकि, लंबी दूरी एवं कम लागत वाला एयरलाइन मॉडल कई एयरलाइनों के लयि एक चुनौती रहा है, जसिमें कई एयरलाइनों की वफिलताएँ तथा कुछ एयरलाइनों का अपेक्षकृत स्थरि एवं लाभदायक संचालन शामिल हैं।

## लंबी दूरी, कम लागत वाला हवाई यात्रा मॉडल क्या है?

- परचिय:
  - लंबी दूरी, कम लागत वाला हवाई यात्रा मॉडल कम लागत वाले वाहक वमिानों (LCC) द्वारा छोटी दूरी के घरेलू और क्षेत्रीय मार्गों से अलग परचालन का वसितार करने तथा न्यूनतम करिए पर नॉन-स्टॉप, लंबी अवधि की उडानों का परचालन करने का एक प्रयास है।
    - इस मॉडल का लक्ष्य लंबी दूरी की यात्रा के संचालन के लयि समान व्यावसायिक रणनीतयिँ एवं प्रक्रयिओं को लागू करके छोटी दूरी के वमिान यात्रा संचालन क्षेत्र में LCC द्वारा प्राप्त की गयी सफलता को दोहराना है।
- चुनौतयिँ:
  - लंबी दूरी के मार्गों पर बड़े वमिानों के संचालन के लयि उच्च ईंधन लागत।
    - बड़े वमिानों के लयि परचालन लागत में वृद्धि, जैसे अधिक चालक दल, रखरखाव तथा हवाई अड्डा शुल्क आदि।
  - वमिान संचालन के वसितार से तीव्र आवागमन तथा वमिान उपयोग के उच्च स्तर को बनाए रखने में कठनिता होती है, परंतु यही वशिषता LCC बजिनेस मॉडल की सफलता के लयि महत्त्वपूरण है।
  - लंबी दूरी यात्राओं पर यात्रयिँ के आराम एवं सुवधिओं की आवश्यकता को LCC की भाँत लागत कम करते हुए संतुलति करना।
  - एक व्यवहारिक नेटवर्क और उडान समयसारणी स्थापति करना, जो लंबी दूरी तथा कम घनत्व वाले मार्गों पर यात्रयिँ की संख्या तथा आर्थिक लाभप्रदता को बनाए रख सके।
  - लंबी दूरी के अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर, पूर्वस्थापति मज़बूत ब्रॉंड पहचान वाले वमिाननसेवा वाहकों से प्रतसिपर्धा करना।
- उदाहरण:
  - स्कूटर, जेटस्रार और फ्रेंच B जैसे कुछ लंबी दूरी के LCC स्थरि और लाभदायक वमिान संचालन करने में सफल रहे हैं।
  - प्रमुख रणनीतयिँ में प्रीमियम/बजिनेस क्लास सुवधिओं के साथ उपहार देना, कम यातायात वाले मार्गों को लक्षति करना तथा मज़बूत घरेलू/क्षेत्रीय नेटवर्क का लाभ उठाना शामिल है।

## भारत के वमिानन क्षेत्र की प्रगतिक्या है?

- भारत के वमिानन क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि:
  - संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत वशि्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू वमिानन बाज़ार बनकर उभरा है।
    - वमिानन उद्योग ने एक उल्लेखनीय प्रगतिकरते हुए अपनी पूर्व सीमाओं को पार कर लयिा है तथा यह एक जीवंत और

प्रतस्पर्धी क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है।

- सरकार की सक्रिय नीतियों और रणनीतिक पहलों ने विमानन क्षेत्र के विकास को प्रेरित किया है, वसति एवं नवाचार के लिये अनुकूल वातावरण को बढ़ावा दिया है।

#### ■ बुनियादी ढाँचे का विकास:

- भारत के हवाई नेटवर्क में एक उल्लेखनीय परिवर्तन देखा गया है, इसके परिचालन हवाई अड्डों की संख्या वर्ष 2014 में 74 की तुलना में दोगुनी होकर अप्रैल 2023 में 148 हो गई है, जिससे लोगों की हवाई यात्रा तक पहुँच में वृद्धि हुई है।

##### ● कक्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना-UDAN:

- कक्षेत्रीय संपर्क योजना-उड़ें देश का आम नागरिक (RCS-UDAN) वर्ष 2016 में शुरू की गई थी ताकि देश में वायुसेवा का वसति किया जा सके।
- इस योजना का उद्देश्य मौजूदा हवाई पट्टियों और हवाई अड्डों को पुनर्जीवित करना, अलग-थलग समुदायों तक आवश्यक हवाई यात्रा की पहुँच में वृद्धि करना और कक्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
- 517 RCS मार्गों के संचालन और 76 हवाई अड्डों को जोड़ने के साथ, उड़ान ने 1.30 करोड़ से अधिक लोगों के लिये हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान की है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है।

#### ■ यात्री वृद्धि:

- यात्री मांग में वृद्धि के साथ, विमानन उद्योग कोवडि के बाद उल्लेखनीय पुनरुत्थान का अनुभव कर रहा है।
  - जनवरी से सितंबर 2023 तक, घरेलू एयरलाइंस ने 112.86 मिलियन यात्रियों का परिवहन किया, जो वर्ष 2022 से इसी अवधि की तुलना में 29.10% अधिक है।
  - अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस ने जनवरी और सितंबर 2023 के बीच 45.99 मिलियन यात्रियों का परिवहन किया, जो वर्ष 2022 से इसी अवधि की तुलना में 39.61% अधिक है।

#### ■ कार्बन तटस्थता:

- नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने देश में हवाई अड्डों पर कार्बन तटस्थता और शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में काम करने की पहल की है।
  - हवाई अड्डा संचालकों को कार्बन उत्सर्जन का मानचित्रण करने और चरणबद्ध तरीके से कार्बन तटस्थता एवं शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में कार्य करने की सलाह दी गई है।
- ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को अपनी विकास योजनाओं में कार्बन तटस्थता और शुद्ध शून्य उत्सर्जन को प्राथमिकता देने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है।
  - दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बंगलूर जैसे हवाई अड्डों ने लेवल 4+ ACI मान्यता प्राप्त कर ली है तथा कार्बन तटस्थ बन गए हैं।
  - 66 भारतीय हवाई अड्डे 100% हरित ऊर्जा पर काम कर रहे हैं।

## भारत के विमानन उद्योग के सामने क्या चुनौतियाँ हैं?

#### ■ उच्च ईंधन लागत:

- विमान टर्बाइन ईंधन (ATF) का खर्च किसी एयरलाइन की परिचालन लागत का 50-70% हो सकता है और आयात कर वित्तीय बोझ को बढ़ाते हैं।

#### ■ डॉलर पर निर्भरता:

- डॉलर की दर में उतार-चढ़ाव का असर लाभ पर पड़ता है क्योंकि विमान अधिग्रहण और रखरखाव जैसे प्रमुख खर्च डॉलर में होते हैं।

#### ■ आक्रामक मूल्य निर्धारण:

- यात्रियों को आकर्षित करने के लिये एयरलाइंस अक्सर आक्रामक मूल्य प्रतस्पर्धा में संलग्न रहती हैं, जिससे उच्च परिचालन लागत के बीच लाभ मार्जिन कम हो जाता है।

#### ■ सीमिति प्रतस्पर्धा:

- वर्तमान में इंडिया और एयर इंडिया के पास विमानन सेवा क्षेत्र में बहुमत हस्तिदारी है, संभवतः संयुक्त रूप से लगभग 70% के करीब। शक्ति का यह संकेंद्रण इनमें से नमिन को जन्म दे सकता है:
  - सीमिति प्रतस्पर्धा: कम अभिकर्ताओं के साथ, मार्गों पर कम प्रतस्पर्धा का जोखिम है, जिससे संभावित रूप से उपभोक्ताओं के लिये अधिक करिया हो सकता है।
  - मूल्य निर्धारण शक्ति: प्रमुख एयरलाइनों के पास टिकट की कीमतों को प्रभावित करने के लिये अधिक अर्जति लाभ हो सकता है, खासकर अगर वे रणनीतियों का समन्वय करते हैं।

#### ■ जमींदोज जहाज़ी बेड़ा:

- सुरक्षा चिंताओं और क्षमता में बाधा बनने वाले वित्तीय मुद्दों के कारण भारतीय हवाई जहाज़ों का एक बड़ा हस्ति (एक चौथाई से अधिक) उड़ान से बाहर है।

#### ■ पर्यावरणीय चिंता:

- कार्बन उत्सर्जन को कम करने और सतत् प्रथाओं को अपनाने का दबाव विकास रणनीतियों में कठिनाई उत्पन्न कर सकता है।

## विमानन उद्योग से संबंधित भारत की पहल:

#### ■ उड़ान योजना (उड़ें देश का आम नागरिक)

#### ■ राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति, 2016

- घरेलू रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (MRO) सेवाओं के लिये वसतु एवं सेवा कर (GST) की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई।

## ■ ओपन स्काई संधि

- नरिबाध यात्रा के लिये **डिजी यात्रा**: यह डिजिटल प्लेटफॉर्म चेहरे की पहचान और कागज़ रहति चेक-इन जैसी सुविधाओं के साथ हवाई यात्रियों के लिये संपर्क रहति अनुभव की सुविधा प्रदान करता है।

# उड़ान योजना

## (उड़े देश का आम नागरिक)

### परिचय:

- > यह एक क्षेत्रीय संपर्क योजना है।
- > इसे वर्ष **2016** में लॉन्च किया गया।
- > यह योजना **10** वर्षों की अवधि के लिये परिचालित की गई है।
- > उड़ान (**UDAN**) योजना का विस्तृत रूप "**Ude Desh ka Aam Nagrik**" है।
- > इसे राष्ट्रीय नागर विमानन नीति-2016 के अनुसरण में तैयार किया गया है।
- > इसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत क्रियान्वित किया गया।

### उड़ान योजना के विभिन्न चरण:

- > **उड़ान 1.0**: इस चरण में **70** हवाई अड्डों के लिये **128** उड़ान मार्गों को **5** एयरलाइन कंपनियों को प्रदान किया गया।
- > **उड़ान 2.0**: उड़ान योजना के दूसरे चरण के तहत पहली बार हेलीपैड भी योजना से जोड़े गए थे।
- > **उड़ान 3.0**: इसमें टूरिस्ट रूट, वाटर एयरोड्रोम को जोड़ने के लिये सीप्लेन और नॉर्थ-ईस्ट कनेक्टिविटी शामिल हैं।
- > **उड़ान 4.0**: वर्ष 2020 में उड़ान योजना के चौथे चरण के तहत **78** नए मार्गों के लिये मंजूरी दी गई थी।
- > **उड़ान 4.1**: इस चरण में सागरमाला सीप्लेन सेवाओं के तहत नए रूट भी प्रस्तावित किये गए हैं।
- > **लाइफलाइन उड़ान**: कोविड-19 के समय में पूरे भारत में मेडिकल कार्गो और आवश्यक आपूर्ति का हवाई परिवहन।
- > **कृषि उड़ान**: कृषि उत्पादों के परिवहन में किसानों की सहायता करना
- > **अंतर्राष्ट्रीय उड़ान**: भारत के छोटे शहरों को कुछ प्रमुख विदेशी गंतव्यों से सीधे जोड़ने के लिये परिचालित किया गया है।

## विशेषताएँ

- > हवाई सेवा के माध्यम से छोटे और मध्यम शहरों को बड़े शहरों से जोड़ना।
- > सस्ती, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और लाभदायक हवाई यात्रा प्रदान करना।
- > असेवित और कम सेवा वाले हवाई अड्डों से संचालन को प्रोत्साहित करने के लिये चयनित एयरलाइनों को वित्तीय प्रोत्साहन देना।
- > कुछ उड़ानों पर लेवी के माध्यम से योजना के वित्तीयन के लिये एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी फंड बनाना।



//

## आगे की राह

- **ईंधन स्रोतों का वविधीकरण**: ईंधन मशिर्ण में जैव ईंधन को शामिल करने, पारंपरिक ATF पर नरिभरता और आयात करों के प्रभाव को कम

करने के लिये पहल करने की आवश्यकता है।

- ईंधन की कीमतों की अस्थिरता को प्रबंधित करने के लिये **ईंधन के बचाव (fuel hedging)** की रणनीतियों को लागू करना, जो कई अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों द्वारा उपयोग की जाने वाली व्यवस्था है।
- **सहायक राजस्व धाराएँ:** लाभ बढ़ाने के लिये कार्गो सेवाओं, इन-फ्लाइट बकिरी और प्रीमियम सेवाओं जैसी सहायक राजस्व धाराएँ विकसित करने की आवश्यकता है।
- **प्रतस्पर्धी मूल्य निर्धारण रणनीतियाँ:** मूल्य निर्धारण को अनुकूलित करने के लिये उन्नत उपज प्रबंधन प्रणालियों का उपयोग करना और नुकसानदेह मूल्य प्रतस्पर्धा (detrimental price wars) में शामिल हुए बिना लाभप्रदता बनाए रखना है।
  - दोबारा व्यापार को प्रोत्साहित करने और आक्रामक मूल्य निर्धारण रणनीति की आवश्यकता को कम करने के लिये ग्राहक नष्टि कार्यक्रमों को मजबूत करने की आवश्यकता है।
- **वनियामक सुधार:** वनियामक सुधारों की वकालत करना जो नए प्रवेशकों को प्रोत्साहित करने और उद्योग में एकाधिकारवादी प्रथाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है।
- **मार्ग युक्तिकरण:** एयरलाइनों को कम सेवा वाले मार्गों का पता लगाने के लिये प्रोत्साहित करना, जिससे प्रतस्पर्धा बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प प्राप्त हो सकेंगे।
  - परिचालन को लचीला बनाए रखने और जहाज़ी बेड़े के स्वामित्व की वित्तीय बोझ को कम करने के लिये, वगैरह के लिये पट्टे की संभावनाओं को ध्यान में रखना।
- **कार्बन ऑफसेट कार्यक्रम:** पर्यावरणीय प्रभाव को मापने और कम करने के लिये **कार्बन उत्सर्जन कैलकुलेटर** जैसे कार्बन ऑफसेट कार्यक्रम को लागू करना।

??????:

**प्रश्न.** बुनियादी ढाँचे के विकास, यात्री वृद्धि और सरकारी नीतियों के प्रभाव जैसे कारकों पर विचार करते हुए भारत के विमानन क्षेत्र की प्रगतिका मूल्यांकन कीजिये।

**UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न**

?????

**प्रश्न.** सार्वजनिक-नज़िी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत संयुक्त उद्यमों के माध्यम से भारत में हवाई अड्डों के विकास की जाँच कीजिये। इस संबंध में अधिकारियों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं? (2017)